



"मध्यप्रदेशमें अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक विकास में ग्रामीण पुस्तकालयों की भूमिका"

शोधार्थी: कविता पुनासे

निर्देशक: डॉ. राकेश कुमार खरे

सारांश

ग्रामीण पुस्तकालयों का मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। अनुसूचित जनजातियाँ ऐतिहासिक रूप से शैक्षिक और सांस्कृतिक प्रतिबंधों का सामना कर रही हैं। इन प्रतिबंधों को दूर करने के लिए, ग्रामीण पुस्तकालयों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ग्रामीण पुस्तकालयों में पुस्तकों के संग्रहण और पुस्तक सामग्री की उपलब्धता का विशेष महत्व है। ये पुस्तकालय अनुसूचित जनजातियों को विभिन्न शैक्षिक सामग्री के साथ परिचित कराते हैं, जो उनके शैक्षिक और सामाजिक विकास में मदद करते हैं। इन पुस्तकालयों में सामूहिक अध्ययन, स्वतंत्र अध्ययन और साक्षरता कार्यक्रमों का संचालन होता है। ये कार्यक्रम अनुसूचित जनजातियों को शिक्षा की प्राप्ति में सहायक होते हैं और उन्हें समाज के साथ एकजुट और समर्थ भूमिका निभाने में मदद करते हैं। इस अध्ययन के नतीजे साबित करते हैं कि ग्रामीण पुस्तकालयों का प्रभावी उपयोग करके अनुसूचित जनजातियों को शैक्षिक संसाधनों तक पहुँचाया जा सकता है, जो उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार, ग्रामीण पुस्तकालयों की भूमिका अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और सामाजिक विकास में अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

कीवर्ड: मध्य प्रदेश, अनुसूचित जनजातियाँ, ग्रामीण पुस्तकालय, शैक्षिक विकास, सामूहिक अध्ययन, स्वतंत्र अध्ययन, साक्षरता कार्यक्रम, सामाजिक विकास, सामग्री, संवेदनशीलता।

I. परिचय

भारत में मध्य प्रदेश राज्य विभिन्न प्रकार के समुदायों का घर है, जिनमें कई अनुसूचित जनजाति (एसटी) या अनुसूचित जाति (एससी) शामिल हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति (एसटी) के रूप में जाना जाता है। इन समुदायों को ऐतिहासिक रूप से सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक हाशिए का सामना करना पड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा और सामाजिक-आर्थिक विकास के अवसरों तक सीमित पहुँच होती है। हाल के वर्षों में, हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाने और उनकी सामाजिक-

आर्थिक प्रगतिको सुविधाजनक बनाने में शिक्षा के महत्वकी मायता बढ़ रही है। हालाँकि, शैक्षिक पहुँच और गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी पहलों और नीतियों के बावजूद, महत्वपूर्ण असमानताएँ बनी हुई हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ बुनियादी ढाँचा और संसाधन अक्सर सीमित होते हैं। इस संदर्भ में, ग्रामीण पुस्तकालय शैक्षिक अंतर को पाटने और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये पुस्तकालय शैक्षिक संसाधनों तक पहुँचने, साक्षरता कार्यक्रमों के लिए सहायता प्रदान करने और ग्रामीण समुदायों के भीतर सीखने की संस्कृतिको बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक विकास को सुविधाजनक बनाने में ग्रामीण पुस्तकालयों की भूमिका को समझना शैक्षिक असमानता

ओंकोदूर करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रभावी हस्तक्षेप और नीतियों को डिजाइन करने के लिए आवश्यक है। यह अध्ययन मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक सशक्तिकरण में ग्रामीण पुस्तकालयों के महत्व

का पता लगाने और सामाजिक-

आर्थिक विकास पर उनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए नीतियों की पहचान करने का प्रयास करता है।

• मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति और उनके प्रकार

क्षेत्र	जनजाति	जिले
उत्तर-पूर्व एमपी	कोल, मड़िया, अगरिया, पनिका, खैरवार	शहडोल, सीधी, जबलपुर, रीवा, सतना
दक्षिणी एमपी	गोडभारिया बैगा, मड़िया, हलबा	मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद
पश्चिमी एमपी	भील, भिलाला	खंडवा, खरगोन, झाबुआ, रतलाम, धार, अलीराजपुर
मध्यम प्रदेश	गोंड, कोरकू	बैतूल, होशंगाबाद, जबलपुर, हरदा, नरसिंहपुर, रायसेन
उत्तर-पश्चिम एमपी	सहरिया, सौर	ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर

• अध्ययन के महत्व:

शैक्षिक असमानताओं का समाधान: यह अध्ययन मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के बीच शैक्षिक असमानताओं को समाधान करने के लिए महत्वपूर्ण है। ग्रामीण पुस्तकालयों के शैक्षिक विकास में उनकी भूमिका की जांच करके, यह अध्ययन इन असमानताओं को कम करने और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के उपायों पर प्रकाश डालता है।

सामाजिक-आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना: शिक्षा सामाजिक-आर्थिक विकास का मुख्य चालक है। ग्रामीण पुस्तकालयों के शैक्षिक विकास में उनकी भूमिका की जांच, समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए नीतियों और अभियानों को सूचित करता है।

शैक्षिक संसाधनों तक पहुँच को बढ़ाना: ग्रामीण पुस्तकालय शैक्षिक सामग्री और संसाधनों के महत्वपूर्ण संग्रहण केन्द्र होते हैं। इस अध्ययन से, संबंधित और गुणवत्ता वाली शैक्षिक सामग्री तक पहुँच में सुधार के तरीके और उपायों को खोजने में मदद मिल सकती है।

स्थानीय समुदायों को सशक्त करना: ग्रामीण पुस्तकालय अक्सर समुदाय के महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं, जो केवल किताबें ही नहीं, बल्कि शैक्षिक कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन भी करते हैं। इस अध्ययन से, स्थानीय समुदायों को उनके शैक्षिक विकास के लिए स्वयं को सशक्त करने के तरीके प्राप्त हो सकते हैं।

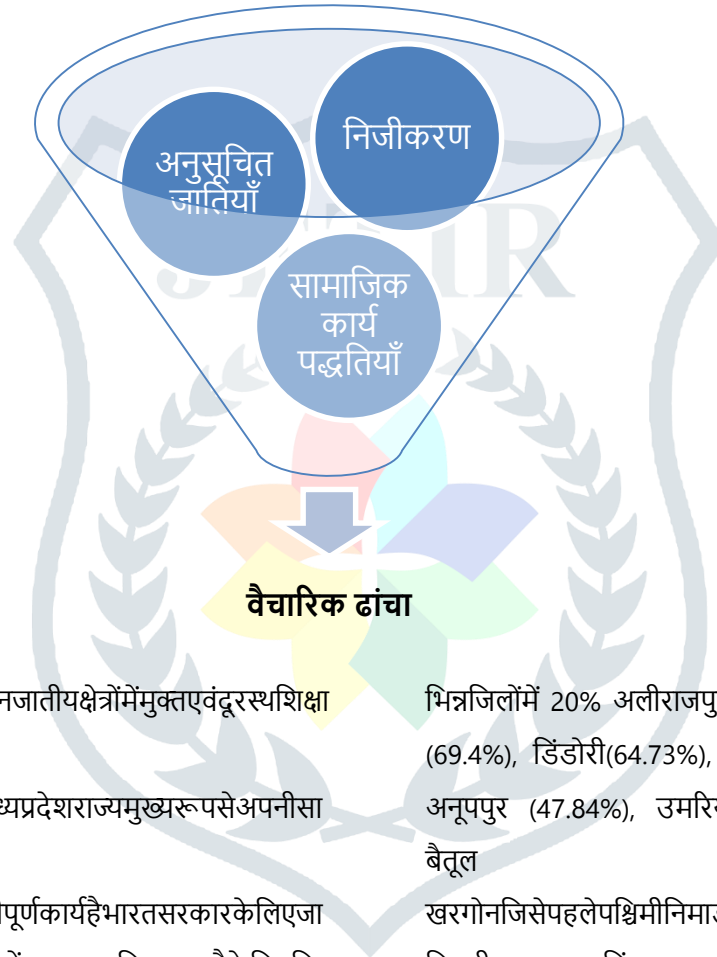
नीति और प्रयोग में अद्यतन: अध्ययन के परिणाम प्राप्त कर्ताओं, शिक्षकों, और प्रयोक्ताओं को शैक्षिक परिणामों को प्रोत्साहित करने में ग्रामीण पुस्तकालयों के प्रभाव के बारे में सूचित कर सकते हैं। इससे सामान्य शिक्षा नीतियों और अभियानों का विकसित होना संभव होता है।

और अधिक अनुसंधान और कार्रवाई को प्रोत्साहित करना: ग्रामीण पुस्तकालयों के शैक्षिक संवेदनशीलता में महत्वपूर्ण योगदान को प्रोत्साहित करने के लिए, यह अध्ययन और भी अधिक अनुसंधान और कार्रवाई को प्रेरित करता है।

• अध्ययन के उद्देश्य:

- मध्यप्रदेशमेंग्रामीणपुस्तकालयोंकेशैक्षिकविकासमेंअपनीभूमिकाकापरिचयप्रदानकरना।
- अनुसूचितजनजातियोंकेबीचशैक्षिकअसमानताओंकेकारणोंऔरप्रभावोंकीविश्लेषणकरना।
- ग्रामीणपुस्तकालयोंकेशैक्षिकसामग्रीऔरसंसाधनोंतकपहुँचकीगुणवत्ताऔरउपयोगिताकामूल्यांकनकरना।
- अनुसूचितजनजातियोंकेशिक्षामेंग्रामीणपुस्तकालयोंकेयोगदानकाप्रभावमापना।
- शैक्षिकऔरसामाजिकविकासकेक्षेत्रमेंनीतियोंऔरकार्रवाईयोंकेलिएसुझावप्रस्तुतकरना।

II. साहित्यसमीक्षा:



अमितचतुर्वेदी(2017)

(ओडीएल)

केमाध्यमसेउच्चशिक्षाकाप्रसारमध्यप्रदेशराज्यमुख्यरूपसेअपनीसामाजिक-

आर्थिकस्थितिकेकारणएकचुनौतीपूर्णकार्यहैभारतसरकारकेलिएजातीयसांस्कृतिकसेटिंग।प्रस्तुतपेपरमेंएकप्रयासकियागयाहैकेलिएवितरणतंत्रमॉडलकेआधारपरप्रभावीओडीएलप्रथाओंकोविकसितकरनेकेलिएबनायागयामध्यप्रदेशकेमुख्यतःआदिवासीक्षेत्रोंमेंउच्चशिक्षाकाप्रसार।यहकियागयाहैविशेषरूपसेमध्यप्रदेशराज्यमें, इसकीजनसंख्याकापांचवांहिससा (21.08 प्रतिशत) देखाजाताहैयहाँजनजातीयजनसंख्याहैजोहमारेदेशकेकिसीभीअन्यराज्यकीतुलनामेंबहुतअधिकहैभारतकेउत्तरपूर्वीराज्योंकोछोड़करजहाँजनजातीयआबादीभीकाफीअधिकहै।परदूसरीओर, उच्चशिक्षामेंआदिवासीआबादीकेओडीएलकानामांकनहिससालगभगहै2

प्रतिशतजोजनजातीयलोगोंकीजनसंख्याहिससेदारीकोदेखतेहुएकाफीकमहै।जहाँतकराज्यहैजहाँतकमध्यप्रदेशकाप्रश्नहै, यहाँजनजातीयजनसंख्याकासंकेन्द्रणअपेक्षाकृतअधिकहैएमपीकेवि

भिन्नजिलोंमें 20% अलीराजपुर (89%), झाबुआ (87%), बड़वानी (69.4%), डिंडोरी(64.73%), मंडला (57.95%), धार (55.9%), अनूपपुर (47.84%), उमरिया (46.72%), शहडोल(44.70%), बैतूल (42.3%),

खरगोनजिसेपहलेपश्चिमीनिमाड़केनामसेजानाजाताथा (39%), सिवनी (37.7%), छिंदवाड़ा (36.38%), खंडवाकोपहलेपूर्वीनिमाड़ (35%), सिंगरौली (32.59%) केनामसेजानाजाताथा।भूरणपुर (30.4%), रतलाम (28.2%), हरदा (28.0%) सीधी (27.81%), कटनी (24.60%) शोपुर(23.47%), बालाघाट (22.52%) औरआगरमालवा (21.10%)

जिले।इसूऔरमध्यप्रदेशभोजमुक्तविश्वविद्यालयभोपाल (एमपीबीओयू)

नेउच्चप्रसारकेलिएईमानदारप्रयासकियाहैअपनेनियमितअध्ययनकेंद्रऔरविशेषअध्ययनकेंद्रस्थापितकरकेओडीएलकेमाध्यमसेशिक्षा(एसएससी)

जनजातीयक्षेत्रोंमेंऔरयेकेंद्रमुख्यरूपसेस्नातककार्यक्रमोंकेलिएसक्रियहैं, बैचलरप्रिपरेटरीप्रोग्राम (बीपीपी), औरकंप्यूटरसाक्षरताकार्यक्रम

(सीएलपी)। अधिकांश जनजातियाँ अपने बच्चों का उपयोग करती हैं सहायक सेवाएँ जो कुछ लाएँगी उनके गुजारा करने वाले परिवारों के लिए अतिरिक्त आय। यह है इसलिए नीतियों की जांच करना महत्वपूर्ण है और कार्यक्रमों का पालन किया जा रहा है और उनके साथ ही राज्य में प्रभावी क्रियान्वयन की पहचान करने के लिए विशेष अध्ययन करना सामाजिक-सांस्कृतिक कारक की प्रगति में बाधक हैं अनुसूचितों के बीच साक्षरता और शिक्षा में जनजातियाँ समुदाय और उनसे संबंधित बाधाएँ शिक्षा पर बुनियादी ढाँचा और धन, बनाना साक्षरता बढ़ाने में संतोषजनक प्रगति इन जनसंख्या समूहों के बीच।

प्रियसिंह

(2019)

प्रस्तुत अध्ययन में अनुसूचित जातियों की उच्च शिक्षा की अप्रभावीता के कारणों का विश्लेषण किया गया है और भारत में जनजातियाँ। भौतिक वातावरण के अलावा सामाजिक असमानता और शिक्षा में भेदभाव इस प्रणाली के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में निचली जाति और उच्च जातिके बीच साक्षरता का अंतर पैदा हो रहा है। यह समाज के एक वर्ग को आर्थिक भेदभाव और बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष का सामना करना पड़ता है। यह भी अछूता नहीं है लैंगिक असमानता का अभ्यास।

भाषा विज्ञान और उचित नेटवर्क का अभाव रूकावट डालने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है शिक्षा प्रवाह।

पाठ्यचर्या डिजाइन,

शिक्षण विधियों और संसाधनों पर पुनर्विचार और अभ्यास किया जाना चाहिए शिक्षा प्रणाली में अंतर को पाटने के लिए इसका पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्रणाली उच्च शिक्षा की बुनियादी अवधारणाओं को विकसित करने को ध्यान में रखते हुए इसका पालन किया जाना चाहिए। विकसित देश बनने की दौड़ में आगे बढ़ रही भारत सरकार को अभी भी संघर्ष करना होगा ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा की बुनियादी अवधारणाओं और परिघटना के लिए मजबूत आधार तैयार करना आने वाली पीढ़ियों को एक विकसित और मजबूत राष्ट्र के स्तंभ बनने की दौड़ में खड़ा होना है। सार्वभौमिक संचार भाषाओं के महत्व को नजर अंदाज नहीं किया जाना चाहिए और इसे महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में अवधारणा में जूरी की सीढ़ी जो कि त्रि-

भाषा की प्रत्येक भाषा है सूत्र को समान महत्व दिया जाना चाहिए।

मोहम्मद रज़ीक (2023) भारत एक बर्तन की तरह है जिसमें अलग-अलग लोगों, संस्कृतियों की आबादी के रूप में अलग-अलग रंग-बिरंगे फूल हैं जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों की आबादी उनमें से एक है। भारत एक मात्र सबसे बड़ा राष्ट्र है जिसके पास है सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या 8.6% (भारत की जनगणना, 2011)। यहाँ लगभग 705 अनुसूचित जनजातियाँ हैं भारत (जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार,

2011)। शिक्षा ही परिचय देती है कि सी की स्थिति सामाजिक, आर्थिक याराजनीतिक आदि हो सकती है, लेकिन शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमेशा कुछ न कुछ होता है कमियाँ, चुनौतियाँ या बाधाएँ। हालाँकि अनुसूचित जनजातियों की आबादी अपनी शिक्षा में सुधार कर रही है स्थिति लेकिन चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। वर्तमान पेरका उद्देश्य चुनौतियों को इंगित करना है, पिछले शोध अध्ययनों की समीक्षा करके अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा के रास्ते में आने वाली बाधाओं या बाधाओं को दूर करना और विभिन्न ऑनलाइन स्रोतों से एकत्र की गई अन्य माध्यमिक जानकारी और आँकड़े। प्रमुख भाषा, स्कूल दूर होना,

अनुपलब्धता जैसे चुनौतियाँ एक बाधा के रूप में पाई गई स्कूल में बुनियादी ढाँचा और बुनियादी सुविधाएँ, निवास के रूप में दूर दराज के क्षेत्र, कम सामाजिक और आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक और पारंपरिक जीवन शैली, बच्चे की शिक्षा के प्रति माता-पिता की मान्यताएं और दृष्टिकोण और शिक्षक संबंधी मुद्दे जैसे अनुपस्थिति, योग्यता, दूरस्थ क्षेत्र समायोजन, और आखिरी लेकिन प्रभाव डालने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक जनजातियों का मौसमी प्रवासन आदि है,

जिसके परिणामस्वरूप चुनौतियाँ उत्पन्न हुईं अनुसूचित जनजातियों में निम्न शिक्षा। यह शिक्षा ही है जो कि सी भी समुदाय, समाज या राष्ट्र की स्पष्ट छवि दर्शाती है। शिक्षा एक उपकरण या उपकरण की तरह है जो कि सी के भाग्य कारास्ता दिखाता है। दुनिया का सबसे विविधतापूर्ण देश यानी भारत में विभिन्न धर्मों, विचारों और संस्कृतियों वाले लोग हैं,

अनुसूचित जनजातियाँ भी उसी का हिस्सा हैं। अनुसूचित जनजातियों की आबादी अन्य आबादी की तुलना में हाशिये पर है (मिश्रा आर., 2008)। उनके द्वारा पहचाने गए विभिन्न कारणों से भी वे शिक्षा प्राप्त करने में वंचित हैं शोधकर्ता अभी भी उन समस्याओं की पहचान करने और उनका समाधान निकालने में योगदान देने का प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान पेर में विभिन्न अध्ययनों और सांख्यिकीय जानकारी को एकत्र और समीक्षा की गई है चुनौतियों के बारे में जानने के लिए प्रमुख समस्याओं का पता लगाया गया।

विकास कुमार चंदेल (2023) शिक्षा एक शक्तिशाली उपकरण है जो समाज को बदल सकती है; हालाँकि, समाज के कुछ वर्ग अभी भी पिछड़े हुए हैं पंहुच में पीछे। हालाँकि, काउंटी ने स्वतंत्रता के सात दशकों का जश्रमनाया और कई बनाये जनजातीय समुदायों के लिए योजनाएँ और कार्यक्रम। भारत में 705 आदिवासी समुदाय हैं, जिनमें से 75 हैं समुदायों को अधिक असुरक्षित समूह माना जाता है जिन्हें पीवीटीजी के नाम से जाना जाता है। इनमें बैगा जनजाति भी शामिल है वंचित हैं।

येसमुदायमुख्यतःमध्यभारतमेंअच्छीखासीसंख्यामेंपाएजातेहैं।यद्यपि सरकारउनकेसमग्रउत्थानकेलिएप्रयासकररहीहै, फिरभीस्थितिजसकीतसबनीहुईहै।शिक्षाकेमहत्वकोसमझतेहुएसरकारनेआश्रमकेरूपमेंअनेकप्रयासकियेहैंहालाँकि, स्कूल, मॉडलस्कूल, आदिवासीस्कूलऔरएकलव्यविद्यालय, आदिवासीसाहित्यिकरिपोर्टकरतेहैं 50.6 प्रतिशतहोना। यहपेपरचयनितगैरसरकारीसंगठनोंकेप्रयासोंकापतालगानेकाएकअनूठाप्रयासकरताहैशिक्षाविकासहेतुमध्यभारतकामैकालक्षेत्र; उनगैरसरकारीसंगठनोंमेंपरिवारशिक्षाशामिलहैसमाज, प्रणामनर्मदायुवासंघ, श्रीरामकृष्णविवेकानन्दसेवाश्रम, जनजातीयकल्याणकेंद्रआदिअध्ययनमेंउनकेप्रयासों, रणनीतियोंऔरकामकाजकेतरीकेकाविस्तृतविवरणदियागयाहैशिक्षाविकासकेलिए। इसकेअलावायहभीजांचकीजातीहैकिसमुदायकेलिएकौनसीसामाजिककार्यपद्धतियोंकाउपयोगकियाजाताहैलामबंदी, संगठनऔरसंबंधनिर्माण।अध्ययनक्षेत्र (मैकलहिल्सरेज) भौगोलिकदृष्टिसेपृथकहै, जहांअनुपपुर, मंडलाऔरडिंडोरीआदिवासीहैंसंकेन्द्रितजिले। आदिवासीसमुदायकाअपनाहैस्वदेशीसंस्कृति, रीति-रिवाजऔरअनौपचारिकशिक्षाप्रणालीजिसकेप्रभावसेधीरे-धीरेगिरावटआरहीहैआधुनिकता। जनजातियोंकीसाक्षरतादरबहुतकमहैराष्ट्रकीसाक्षरता, जबकिमैकलजनजातियोंकीसाक्षरताबहुतअधिकहैगरीब।

साधनासक्सेना(2020)

यहपेपरपिछलेतीनदशकोंमेंशिक्षामेंआएछोटेबदलावोंपरनजरडालताहैमध्यप्रदेशकापिपरियानामकशहर।पिपरियाअपनेस्थानऔरसमुद्रइतिहासकेकारणअद्वितीयहैसामाजिकआंदोलन।दशकोंकेनव-उदारवादीसुधारोंनेपिपरियाकाशहरीकरणनहींकियाहैऔरयहबनाहुआहैकिसीभीबुनियादीढांचकेविकास, उद्योग, औरनिजीयासरकारद्वारासंचालितस्वास्थ्यसेवंचितशिक्षासुविधाएं। हालाँकि, शिक्षामेंनिजीकरणकीनीतियोंनेपिपरियाकोप्रभावितकियाहैकईमायनोंमेंस्कूलप्रणाली, जिसमेंसर्वश्रेष्ठसरकारीस्कूलोंकीगिरावटऔरशामिलहैनिजीस्कूलखोलेगए, जिसकेपरिणामस्वरूपमध्यमवर्गराज्यसंस्थानोंसेबाहरहोगया।यहपेपरशहरकेलोगोंकीबदलतीशैक्षिकऔरव्यावसायिकआकांक्षाओंकीपड़तालकरताहै।हाशिएपररहनेवालेसमुदायोंकेलिएविकल्पकुछनिचलेस्तरकेशिक्षणकेलिएप्रतिस्पर्धातकसीमितहैं, बैंकिंग,

औरनौकरशाहीनौकरियाँ।इसलिएशिक्षाकानिजीकरणसामाजिकदयाराबढ़ाकरहैऔरआर्थिकविभाजनतथाबढ़तीअसमानताएँ।पिपरियाकीविशिष्टताकईकारकोंकेसंयोजनसेउत्पन्नहोतीहै, जैसेइसकीभौगोलिकस्थिति, समृद्धसमाजवादीइतिहासऔरअनेकसमुदाय।इसमेंठहरावऔरकमीकाभीअनुभवहुआहैहालकेवर्षोंमेंविकासकेअवसर।पिपरियाकीअर्थव्यवस्थाकृषिपरनिर्भरहैभीतरीइलाकोंसेउपजऔरअनाजमंडी, कृषिव्यवसायऔरव्यापारकेईर्द-गिर्दघूमतीहै।कोईबुनियादीढांचागतयाऔद्योगिकविकासनहींहुआहै।परिवहन, स्वास्थ्यऔरस्वच्छतासुविधाएंअल्पविकसितबनीहुईहैं।

प्रमा चटर्जी(2016)आधुनिक समाज में शिक्षा का बहुत महत्व है इसलिए अक्सर शिक्षा का महत्व होता है उज्ज्वल भविष्य की कुंजी कहा जाता है। भारतीय इतिहास में हम पाते हैं कि गैर-आदिवासी समूहों ने शिक्षा की सहायता से लाभान्वित हुए हैं, परन्तु जनजातियाँ सामाजिक दृष्टि से पिछड़ी हुई हैं। आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से। शिक्षा जनजातीय समुदायों सहित सभी के लिए महत्वपूर्ण है। हालाँकि भारत सरकार ने विकास की दिशा में कई कदम उठाए हैं आदिवासी समुदायों का शिक्षा स्तर लेकिन उनका शिक्षा स्तर खराब रहता है। इस कगज जहाँ मध्य प्रदेश के आदिवासी समुदायों की शैक्षिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया गया है राज्य की जनसंख्या का 21.1% हिस्सा अनुसूचित जनजाति का है (72.62 मिलियन में से 15.31 मिलियन), 2011 की जनगणना के अनुसार। पेपर को द्वितीयक डेटा की मदद से पूरा किया जाता है जो विभिन्न स्रोतों से एकत्रित किये गये हैं। यह पेपर समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करता है जनजातियों में शिक्षा के संबंध में। सामाजिक विकास के लिए शिक्षा एक मूलभूत आवश्यकता है। उचित के बिना अनुसूचित जनजाति की शिक्षा, विकास कल्पना से परे है। बड़ी संख्या में हैं भारत में जनजातीय समूहों की। प्रत्येक समूह की अपनी संस्कृति, सामाजिक प्रथा, बोलियाँ, व्यवसाय। उन्हें समाज का वंचित वर्ग माना जाता है।

अम्मान मदन(2012) भारत में सामाजिक असमानता और वास्तविक स्तर पर शिक्षा के बीच कनेक्शन, नामंजूर होने की तुलना में, प्रवेश में असमानता के पैटर्न की तुलना में इतनी अच्छी तरह समझी नहीं जाती है। दक्षिणी मध्य प्रदेश के जनजातियों के एक आदिवासी बेल्ट में 23 पड़ोसी और समान सरकारी प्राथमिक विद्यालयों का अध्ययन किया गया था ताकि छात्रों के गणित और भाषा अंकों का संदर्भिय कारकों के साथ संबंध मिल सके। इसमें छात्रों का लिंग, भौगोलिक स्थान, बाहरी एजेंसी द्वारा प्रदान की

जाने वाली विद्यालयीन सहायता और उनके माता-पिता की जाति, वर्ग, लिंग, राजनीतिक प्रभाव और शिक्षा जैसे विभिन्न संदर्भिय कारकों को शामिल किया गया। अन्य कारकों को नियंत्रित करने के बाद आंकड़ों का पार्श्विक विश्लेषण किया गया। अध्ययन में विद्यार्थियों के अकादमिक अंकों के लिए सबसे बड़े सहायक अकारक माता-पिता की शिक्षा और उनका राजनीतिक प्रभाव पाया गया। जाति और वर्ग महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं थीं, लेकिन उनका योगदान अपेक्षाकृत कम था। लिंग सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण था लेकिन अंकों के साथ उसका सबसे कम संबंध था। उपलब्ध बाहरी सहायता उस प्रकार की थी जो अधिकारियों और अवैतनिक के बीच की अंतर को कम करने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन इस रूप में वर्तमान स्थिति में यह इसे कभी भी मिटाने की संभावना नहीं थी। परिणाम भारतीय शिक्षा समाजशास्त्र में कुछ सिद्धांतों को पुनः विचार करने की आवश्यकता का सुझाव देते हैं। कुछ प्रणालीगत कमियाँ स्पष्ट हैं जबकि अन्य को उजागर करने के लिए थोड़ी खोजबीन की आवश्यकता है। सबसे अधिक दिखाई देने वाली हानियाँ पहुँच की प्रक्रिया में देखी जाती हैं। कुछ प्रकार की शिक्षा बहुत आगे ले जाती है उच्च पद और धन तक अधिक आसानी से। इन्हें कई सरकारों में प्रलेखित किया गया है, एनजीओ और अकादमिक रिपोर्ट।

माल्याद्री, पाचा(2012) भारतीय संविधान ने अनुसूचित जनजातियों (एसटी) को विशेष स्थान दिया है। पारंपरिक रूप से आदिवासियों, वनवासियों, जनजातियों या आदिवासियों के रूप में संदर्भित; एसटी भारतीय जनसंख्या के लगभग 8% को गठित करते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले लगभग 573 अनुसूचित जनजातियाँ हैं, जो अपनी भाषा के माध्यम से अलग होती हैं, जो उनके रहने के राज्य में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा से भिन्न होती है। भारत में 270 से अधिक ऐसी भाषाएँ हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार, भारत में जनजातियों की जनसंख्या लगभग 67.8 मिलियन है। सबसे अधिक आदिवासी मध्य प्रदेश (16.40 मिलियन), उड़ीसा (7 मिलियन) और बिहार (6.6 मिलियन) में है। हालांकि, कुल जनसंख्या में आदिवासियों का सबसे अधिक आंकड़ा मिजोरम (95%), लक्षद्वीप (93%), नागालैंड (88%), मेघालय (86%), और अरुणाचल प्रदेश (64%) में है। नौ

राज्य - मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, और पश्चिम बंगाल; भारत में आदिवासी जनसंख्या का चौथाई से अधिक हिस्सा है। संविधान में कहीं भी जाति या आदिवासी की परिभाषा नहीं है हालांकि, अनुच्छेद 342 के अनुसार, एसटी उन जातियों या आदिवासी समुदायों का प्रतिनिधित्व करता है जो राष्ट्रपति द्वारा सूचित किए गए होते हैं। जनजातियाँ पारंपरिक हिन्दू जाति व्यवस्था का हिस्सा नहीं हैं। भारत में एसटी "आदिवासी" या "स्थानीय जनजाति" के अन्य भागों के तरह हैं। साम्प्रदायिक जीवन जनजाति समाज का एक मौलिक पैरामीटर बनाता है। यह विभिन्न त्योहारों और सांस्कृतिक उत्सवों के माध्यम से प्रकट होता है। अगर शिक्षक इन अवसरों में भाग लेते हैं और जनजाति संस्कृति का उचित सम्मान देते हैं, तो वह गांव में एक अच्छे शैक्षिक केंद्र का निर्माण कर सकती हैं। जनजाति गांव में, शिक्षक को एक अध्यापक के रूप में, और विशेष रूप से स्थानीय ज्ञान के 'खोजनेवाला' के रूप में, जनजाति संस्कृति से स्थानीय ज्ञान का अध्ययन करना चाहिए, जो अंत में एक वैश्विक ज्ञान में परिणामित होगा। शिक्षा में मौखिक परंपरा एक महत्वपूर्ण उपकरण होना चाहिए, जो एक जनजाति के बच्चे के व्यक्तित्व को उसके स्वयं के सांस्कृतिक परिवेश से विकसित करने में मदद करेगा, घर और स्कूल के परिवेश से अलग किए गए एक कृत्रिम धुंधले व्यक्तित्व को नहीं बनाएगा। साम्प्रदायिक जीवन जनजाति समाज का एक मौलिक मापदंड बनाता है। यह विभिन्न त्योहारों और सांस्कृतिक उत्सवों के माध्यम से प्रकट होता है। अगर शिक्षक इन अवसरों में भाग लेते हैं और जनजाति संस्कृति का उचित सम्मान देते हैं, तो वह गांव में एक अच्छे शैक्षिक केंद्र का निर्माण कर सकती हैं। जनजाति गांव में, शिक्षक को एक शिक्षार्थी होना चाहिए, और विशेष रूप से जनजाति संस्कृति से स्थानीय ज्ञान का 'खोजक' होना चाहिए, जो अंत में एक वैश्विक ज्ञान में परिणामित होगा। शिक्षा में मौखिक परंपरा एक महत्वपूर्ण उपकरण होना चाहिए, जो जनजाति के बच्चे के व्यक्तित्व को उसके स्वयं के सांस्कृतिक परिवेश से विकसित करने में मदद करेगा, घर और स्कूल के परिवेश से अलग किए गए एक कृत्रिम धुंधले व्यक्तित्व को नहीं बनाएगा।

III. शोधकीकमी:

प्रदान किए गए पाठों के आधार पर, एक संभावित अनुसंधान की कमी का संकेत हो सकता है भारत में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बीच शिक्षा में होने वाली शिक्षा की असमान

ताओं को संबोधित करने के लिए सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों की प्रभावकारिता का एक व्यापक विश्लेषण की आवश्यकता है। हालांकि, पाठों में विभिन्न चुनौतियों और पहलों का स्पर्श है, लेकिन किसी विशेष हस्तक्षेपों का विस्तृत विश्लेषण,

उनके आधारशीलस्तरपरकार्यान्वयन, औरमार्जितसमुदायोंकेलिएगुणवत्ताशिक्षाकेपहुंचकोसुधारनेपरउनकाप्रभावपरगराजाँचकाअभावहोसकताहै।इसकेअतिरिक्त, भूगोल, आर्थिकस्थिति, सांस्कृतिकबाधाएँ, औरलिंगजैसेकारकोंकेसंगतिकताकाअध्ययनभीसीमितहोसकताहै, जोइनसमुदायोंकेशिक्षामेंहोनेवालीअसमानताओंकेसंदर्भमें।इनपहलुओंकीजाँचसेनीतिनिर्माताओंऔरप्रबंधनकर्ताओंकेलिएमहत्वपूर्णअनुमानप्राप्तहोसकतेहैं, जिन्हेंसमावेशीशिक्षाकेलिएअधिकनिश्चितऔरप्रभावीरणनीतियोंकाडिज़ाइनकरनेकेलिएअच्छेदिशानिर्देशप्राप्तहोसकतेहैं।

IV. अनुसंधानपद्धति:

सांख्यिकीयविश्लेषण:प्राथमिकडेटासंग्रहकेलिए, ग्रामीणक्षेत्रोंमेंस्थितअनुसूचितजनजातिकेसाक्षात्कार, साक्षरतास्तरकाजांच, औरपुस्तकालयोंकीसामग्रीकाविश्लेषणकियाजाएगा।

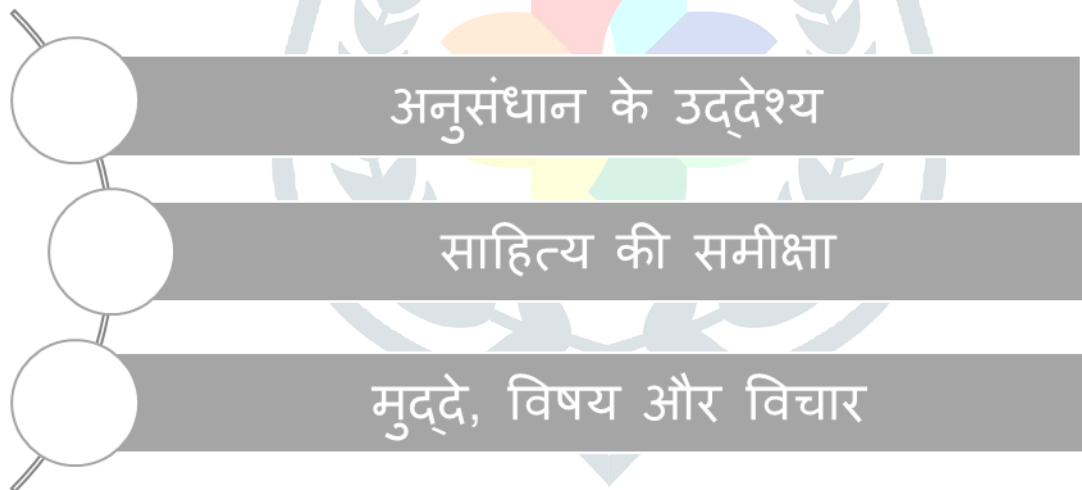
संगठितसाक्षात्कार:ग्रामीणपुस्तकालयोंकेप्रबंधकों, सामुदायिकनेताओं, औरअन्यस्थानीयप्रतिष्ठानोंकेसाथसंगठितसाक्षात्कारकिएजाएंगेताकिउनकीदृष्टिकोणसेग्रामीणपुस्तकालयोंकेशैक्षिकयोगदानकामूल्यांकनकियाजासके।

प्रायोगिकअध्ययन:

चयनितकुछगाँवोंमेंप्रायोगिकअध्ययनकियाजाएगा, जिसमेंग्रामीणपुस्तकालयोंकीप्रभावीता, सामाजिकसहयोग, औरशैक्षिकपरिणामोंकामूल्यांकनकियाजाएगा।

तुलनात्मकअध्ययन:अन्यराज्योंऔरक्षेत्रोंमेंग्रामीणपुस्तकालयोंकेशैक्षिकयोगदानकेसाथमध्यप्रदेशकातुलनात्मकअध्ययनकियाजाएगा।

प्रस्तावनाऔरविश्लेषण:अध्ययनकेआधारपरग्रामीणपुस्तकालयोंकेशैक्षिकयोगदानकेप्रस्तावितसुधारोंकाविश्लेषणकियाजाएगा, जोअनुसूचितजनजातियोंकेशैक्षिकऔरसामाजिकविकासमेंसहायकसाबितहोसकतेहैं।



चित्र 1. डेटा संग्रह पथ

V. भविष्यकाक्षेत्र

अध्ययनकेभविष्यकेक्षेत्रमें, एकमहत्वपूर्णपहलहैग्रामीणपुस्तकालयोंकेशैक्षिकयोगदानकोऔरभीप्रभावशालीऔरसक्रियबनानेकेलिएउपायोंकापरिकल्पनाकरना।इसमेंशामिलहैग्रामीणक्षेत्रोंमेंअनुसूचितजनजातियोंकेशैक्षिकसंगठनकोसुदृढ़करनेकेलिएपुस्तकालयोंकीभूमिकामेंसंभावितपरिवर्तनोंकामूल्यांकन, सामाजिकसंगठनोंऔरस्थानीयप्रशासनकेसाथसहयोगकरनेकेलिएनिर्देशकसूचनाकाविकास, औरग्रामीणक्षेत्रोंमेंशैक्षिकपरिणामोंकोसुधारनेकेलिएशैक्षिकनीतियों

कासंशोधन।यहअध्ययनभविष्यमेंसंवेदनशीलऔरस्थायीशैक्षिकनेतृत्वकेविकासकोप्रोत्साहितकरनेकेलिएमहत्वपूर्णहोसकताहैऔरअनुसूचितजनजातियोंकोउचितशिक्षासंसाधनोंतकपहुँचनेमेंसहायकहोसकताहै।

VI. निष्कर्ष

अध्ययनकापरिणामदर्शाताहैकिग्रामीणपुस्तकालयोंकामध्यप्रदेशमेंअनुसूचितजनजातियोंकेशैक्षिकविकासमेंमहत्वपूर्णयोगदानहै।इनपुस्तकालयोंकीसहायतासेअनुसूचितजनजातियोंकोउचितशिक्षासामग्री,

साक्षरताकार्यक्रमों और सामाजिक संगठन की सेवाएं प्राप्त होती हैं। इस अध्ययन के आधार पर, हम सुझाव प्रस्तुत करते हैं कि सरकारी नीतियों में ग्रामीण पुस्तकालयों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए, उनके विकास के लिए समर्थन प्रदान किया जाना चाहिए, और उनकी संगठना और प्रबंधन में उन्नतिकी जानी चाहिए। इसके अलावा, सामुदायिक सहयोग, सामाजिक संगठनों के साथ साझेदारी, और सरकारी सहायता के माध्यम से इन पुस्तकालयों के शैक्षिक योगदान

1. राजीक, एम. (२०२३). भारत में अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा में चुनौतियाँ और बाधाएँ: एक अवलोकन। दिसंबर, ०-८।
2. जिले, टी. (२०१७). ओडीएल के माध्यम से उच्च शिक्षा के प्रसार का मूल्यांकन। १२(२), ३७-४८।
3. सिंह, प., और कुमार, एल. (२०२०). समीक्षा: मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में संघटित जाति और जनजातियों के उच्च माध्यमिक शिक्षा के प्रभाव पर उच्चतर शिक्षा का प्रभाव। ६।
4. चंदेल, वी. के., रथौर, एन. एस., और रमेश, बी. (२०२३). जनजाति शिक्षा के लिए नागरिक समाज संगठनों के प्रयास: मध्य भारत के मैकल क्षेत्र से प्रतिबिम्ब। अगस्त।
5. शिवराम, बी., कुमार, आर., कुमार, एस., नेगी, बी. एस., दलाल, आर. एस., राज, वाई., गुप्ता, आर., सचदेवा, ए., ठाकुर, प., सिंह, प., सोनी, म., कौंडल, एच., और अदेवाले, ओ. (२०२३). हिमाचल प्रदेश।
6. सोनी, वी. के. (२०२१). मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजाति महिलाओं की जनसांख्यिकीय, सामाजिक-आर्थिक, मातृत्व और बाल स्वास्थ्य। फरवरी।
7. घोष, एस. (२०१५). भारतीय राज्यों में विद्यालय शिक्षा में असमानताओं का मापन: भारतीय स्थानीय जनजाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के बीच नामांकन की अंतर्गत अंतर की कमी? २०(३), ५४-७१। <https://doi.org/10.9790/0839-203845871>
8. इस्लाम, एम. एस. (२०२०). निस्सिम एजीकियल की आधुनिक स्थिति और 'रोमांटिक भूतकाल' से 'एक शुद्ध ब्रेक।' अगस्त।
9. चंटिया, ए., और मिश्रा, प. (२०१५). भारत में अनुसूचित जनजातियों के अधिकार: चुनौतियाँ और समस्याएं जनजाति लोग: भारतीय संदर्भ में जनजाति का जनसांख्यिकीय प्रोफाइल। १, ४०-५०।

नको और भी प्रभावशाली बनाया जा सकता है। आखिरकार, इस अध्ययन से हमें यह ज्ञात होता है कि ग्रामीण पुस्तकालयों को शैक्षिक संगठन के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका मिल सकती है, जो अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और सामाजिक विकास को समर्थन करने में सहायक हो सकती है।

VII. संदर्भ :

10. सक्सेना, एस. (संग्रहीत). कोई शीर्षक नहीं।
11. चंदेल, वी. के., रथौर, एस. एस., और रमेश, बी. (२०२३). उच्च शिक्षा में अनुसूचित जनजातियाँ: समस्याएँ और दृष्टिकोण। ५(४), १-८।
12. मदन, ए., और तिवारी, जी. (२००८). सामाजिक असमानता की दृष्टि से शैक्षिक उपलब्धि: एक अध्ययन एक जनजाति के क्षेत्र में अम्मन मदन और घनश्याम तिवारी। मनवा, १-१९।
13. शर्मा, आर. के., और रॉय, जे. (२०१७). तीन सबसे पिछड़े जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक और जनसांख्यिकीय विशेषताएँ मध्य प्रदेश। जनवरी २०१६।
14. सिंह, ए. के. (२०२३). उत्तर प्रदेश में जनजातियों के शैक्षिक विकास। १२(१), २०२३।
15. चटर्जी, प. (२०१९). मध्य प्रदेश में जनजाति समुदायों की शिक्षा की स्थिति। जनवरी।
16. ब्रिजेस, के. (२०१६). जलवायु परिवर्तन, अनुसूचित जातियों, और अनुसूचित जनजातियों: ग्रामीण मध्य प्रदेश में महिला किसानों की सामाजिक-आर्थिक और जलवायु परिवर्तन की भावनात्मकताएं विशेष रूप से महिला किसानों की सामाजिक-आर्थिक और जलवायु परिवर्तन की भावनात्मकताएं विशेष रूप से महिला किसानों की सामाजिक-आर्थिक और जलवायु परिवर्तन की भावनात्मकताएं विशेष रूप से महिला किसानों की सामाजिक-आर्थिक और जलवायु परिवर्तन की भावनात्मकताएं। ५।
17. सोनी, ए. (२०२४). छत्तीसगढ़ के अगारिया जनजाति के माध्यम से औपचारिक शिक्षा के माध्यम से जनजाति विकास। दिसंबर २०२३। <https://doi.org/10.21088/आईजेआरए.२४५४.१११८.१२२३.४>

18. प्रदेश, ए. (२०१२). जनजाति बच्चों के लिए शिक्षा: मानव विकास के लिए एक इंजन। १(१), ९९-१०६।

